दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 11 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 73

राम मंदिर पर समयसीमा के अंदर बनेगा ट्रस्ट:रेड्डी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में केंद्र द्वारा एक योजना तैयार करना शामिल है जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट की या फिर अन्य उपयुक्त संस्था की स्थापना की जाएगी।

उन्होंनें बताया कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, ट्रस्टियों की शक्तियां, ट्रस्ट को भूमि का हस्तांतरण और सभी आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। केंद्र सरकार न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर लिखित में जवाब में कहा, श्संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लगभग 4800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि बहुत से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसानों की आत्महत्या, कृषक और खेतिहर मजदूर को लेकर कोई डाटा नहीं दिया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिनियम में 2 महीने के अंदर जांच और ट्रायल को पूरा करने का प्रावधान है।

कश्मीर में सबकुछ सामान्य

वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा और वहां के मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं देगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सांसद अधीर रंजन चौधरी के पूरक प्रश्न के उत्तर में शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य है, लेकिन वह कांग्रेस की स्थिति सामान्य नहीं कर सकते।

एएसपी के खिलाफ हनन प्रस्ताव

बिहार भाजपा अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल मोतिहारी के एएसपी शैशव यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए। सांसद ने एएसपी पर बिना सबूत के बदनाम करने का आरोप लगाया है।

मेक इन इंडिया, रेप इंडिया में तब्दील: अधीर

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्य है कि हर मुद्दे पर बोलने वाले प्रधानमंत्री इस मामले (महिलाओं के खिलाफ अपराध) पर चुप्पी साधे हुए हैं।

राज्यसभा में हुई हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। हाथ से मैला ढोने पर रोक के बावजूद देश में इसके जारी रहने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को एक मनोनीत सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने कहा कि इस कार्य से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाने के साथ साथ इस प्रथा पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जानी चाहिए।शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए तुलसी ने कहा कि हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद रोजगार के समुचित अवसरों के अभाव में करीब 54,000 लोग हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर हैं।उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की ओर से इन लोगों को न तो सुरक्षा के कोई उपकरण दिए जाते हैं और न ही इनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।तुलसी ने कहा कि गंदगी के संपर्क में आ कर इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होती ही हैं, कई बार मौत भी हो जाती है। बीते तीन साल में इन हालात में जान गंवाने वाले ऐसे लोगों की मौत का आंकड़ा 50 से अधिक है।मनोनीत सदस्य ने कहा कि हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने वाले कानून में सुरक्षात्मक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और निजी ठेकेदार इसी अस्पष्टता का लाभ उठाते हैं।तुलसी ने सरकार से मांग की कि इस कार्य से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाने के साथ साथ इस प्रथा पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण एवं खास

निर्भया फंड से अस्पतालों में बर्न वार्ड बनाने की मांग

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के प्रति गहरी चिंता जताते हुये मंगलवार को राज्यसभा में मांग की कि हाल के दिनों में विभिन्न अपराधों में महिलाओं को जलाने की घटनाओं में वृद्धि होने के मद्देनजर देश में सभी जिला अस्पतालों में निर्भया फंड से बर्न वार्ड बनाया जाना चाहिए। झा ने शून्यकाल के दौरान यह मांग करते हुये कहा कि इस तरह की घटनाओं के पीड़ितों को न:न सिर्फ सर्जरी की बल्कि मानोचिकित्सकीय सलाह की भी जरूरत होती है। इसके लिए हर जिला अस्पताल में बर्न वार्ड बनाया जाना चाहिए । इसके लिए निर्भया फंड या किसी अन्य फंड के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

किराड़ी के फर्नीचर बाजार में लगी आग

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में एक बार फिर आग लगने खबर आ रही है। दिल्ली के किराड़ी इलाके के फर्निचर मार्केट में मंगलवार सुबह अचानल आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुट गई हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाजार में भारी मात्रा में लकड़ी के सामान होने के कारण लोगों के बीच दहशत फैल गई है। खबर है कि आग बाजार के गोदाम वाले हिस्से में लगी है। तीन मंजिला गोदाम 300 स्वायर यार्ड में फैला हुआ है। बता दें कि रविवार को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर चार मंजिला फैक्ट्री में लगी भीषण आग में करीब 43 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या इसलिए ज्यादा थी क्योंकि फैक्ट्री में आने-जाने का एक ही रास्ता रास्ता था और समय रहते लोग नहीं निकल पाए और दम घुटने से ज्यादातर की मौत हो गई। वहीं, दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

असंवैधानिक नागरिकता विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट में होगी लड़ाई: चिदंबरम

नईदिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि इस असंवैधानिक विधेयक पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी. लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 80 वोट. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक है. संसद ने उस विधेयक को पारित किया जो असंवैधानिक है और अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. पूर्व गृह मंत्री ने कहा, निर्वाचित सांसद अपनी जिम्मेदारी को वकीलों और न्यायधीशों के ऊपर डाल रहे हैं. गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की. विधेयक लोकसभा में आसानी से पास हो गया है और अब मोदी सरकार इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश करेगी. बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी और पूर्वोत्तर के कुछ दलों के साथ आने के कारण सरकार को इस बिल को पास कराने में दिक्कत नहीं हुई.

मोदी को मिले उपहारों की नीलामी से मिले 15 करोड़

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों, स्मृति चिन्हों और अन्य की 2015 से 24 अक्टूबर 2019 तक हुई नीलामी से कुल 15.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वदेश में भेंट किए गए स्मृति चिन्हों, उपहारों आदि की नीलामी से कुल 15.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।श् उन्होंने कहा कि यह नीलामियां 18 फरवरी से 20 फरवरी 2015, 27 जनवरी से 1 अप्रैल 2019 और 24 सितंबर से 24 अक्टूबर 2019 के बीच आयोजित की गई। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2014 से पहले

आयोजित नीलामियों का कोई विवरण नहीं मिला है। गौरतलब है कि इसी साल अक्टूबर में हुई ई-नीलामी में महात्मा गांधी के साथ बनाए गए मोदी के चित्र पर सबसे अधिक 25 लाख रुपये की बोली लगी थी। प्रधानमंत्री की अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए एक तस्वीर के लिए 20 लाख रुपये बोली लगाई गई। ई-नीलामी से हुई आमदनी 'नमामि गंगे' मिशन के लिए दान करने की घोषणा की गई थी।

अधिकारों का दावा करते समय अपने कर्तव्यों को न भूले जनता- कोविंद

» मानवाधिकार दिवस

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को मानवाधिकार दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूरे विश्व के लिए मानवाधिकार दिवस मनाने का आदर्श मार्ग आत्मनिरीक्षण है। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पवित्र पाठ की भावना के अनुरूप क्या करना चाहिए।

मानवाधिकार आयोग के मानव

अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए किए गए कार्यों और उसमें लोगों के विश्वास की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भय और पक्षपात के बिना आयोग ने अर्द्धन्यायिक निगरानीकर्ता की भूमिका लोगों की आशाओं के अनुरूप निभाई है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने हंसा मेहता के योगदान को याद किया। हंसा मेहता ने भारत के संविधान के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के कारण पुरुषों के अधिकारों की घोषणा को अंततः मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें मानवाधिकारों में योगदान के लिए विश्व की प्रथम महिला (फर्स्ट लेडी ऑफ़ द वर्ल्ड) भी कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हम मानवाधिकार और लैंगिक समानता के क्षेत्र में हंसा बेन के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करने के लिए और अधिक कार्य कर सकते हैं।

मानवाधिकार चार्टर के अनुरूप समाज को बनाने के लिए लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों में हमारी असफलता, जैसा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में दिखा है, अक्सर मौलिक कर्तव्यों के पालन में हमारी विफलता का संकेत देती है।

जनधन खाताधारकों को अब मिलेगी बड़ी सुविधाएं

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जुड़े खाताधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जन धन योजना में खोले गए खाते में पांच हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा को दोगुना कर दस हजार रुपए कर दिया गया है।

योजना के तहत अब हर परिवार की जगह प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर दिया जाएगा। जन-धन योजना के तहत जो भी नए खाते खुल रहे हैं, उन्हें दो लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल कर दी गयी है। इससे पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ 18 से 60 साल की उम्र के खाताधारकों को ही थी। जीरो बैलेंस से खुलने वाले जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ वही लोग ले सकते हैं, जिनका बैंक खाता छह महीने तक सुचारू रूप से चलेगा और उसमें बैलेंस होगा। रूपे डेबिट कार्ड से एक्टिव ट्रांजेक्शन भी जरूरी है। साथ ही खाता आधार से लिंक होना चाहिए। खाताधारक की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हुई तो बैंक 15 हजार रुपए का ओवरड्राफ्ट एक घंटे में दे देंगे।

बैंक 12 से 16 फीसदी तक लेते हैं ब्याज

जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा का मतलब यह है कि अगर किसी जन-धन खाताधारक के बैंक खाते का रिकॉर्ड अच्छा है तो वह जरूरत पड़ने पर अपने खाते में पैसे न होने पर भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट के तहत बैंक से रकम ले सकता है। यह वास्तव में एक छोटी अवधि का एक लोन है जो बैंक खाते के संचालन की वजह से बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा होने पर जरूरत पड़ने पर साहूकार से ब्याज पर रकम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक इसके एवज में 12 फीसदी से 16 फीसदी तक ब्याज लेते हैं।

चार महीने में सीमा पार से घुसे 59 आतंकवादी

नईदिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले चार महीने में जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के रास्ते 59 आतंकवादियों के देश में घुसने का अनुमान है।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों द्वारा किये जाने वाले घुसपैठ के नियमित प्रयास सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित हैं। अगस्त 2019 से अब तक सीमा पार से ऐसे 84 प्रयास किये गये हैं और अनुमान है कि ऐसे 59 आतंकवादी देश की सीमा में घुस आये हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 से 01 दिसंबर 2019 तक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड 22 हजार 557 आतंकवादी मारे गये हैं। सुरक्षा बलों की प्रभावशाली चौकसी के कारण वर्ष 2005 से 31 अक्टूबर 2019 तक सीमा पास से घुसपैठ के प्रयासों के दौरान 1,011 आतंकवादी मारे गये, 2 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये और 2,253 आंतकवादियों को वापस भागने पर विवश किया गया है।

शाह ने कहा कि दुश्मन द्वारा घुसपैठ के प्रयास जम्मू-कश्मीर में हिंसा पैदा करने और मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के अपने इरादे में सफल होने के लिए, घाटी में आतंकवादियों की घटती हुई संख्या को बढ़ाने हेतु एक छद्म युद्ध के रूप में उनके एजेंडे का हिस्सा है। घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए निरंतर प्रभुत्व कायम रखने, घात लगाने और गश्त लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

ईईपीसी ने 111 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

नईदिल्ली (आरएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन, आवास और शहरी मामले (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार (ईईपीसी) प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2017-18 में 76 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2018-19 में 87 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात स्तर पर पहुंचने के लिए ईईपीसी को बधाई दी। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि अगले वर्ष भारत का इंजीनियरिंग निर्यात एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

इस वर्ष ईईपीसी ने निर्यात पुरस्कारों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और 32 से अधिक उत्पाद पैनलों को आठ श्रेणियों में वर्ष 2017-18 के लिए 111 विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष पहली बार ईईपीसी सदस्य कंपनियों के मूल्यांकन के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) को आमंत्रित किया गया है और सात विजेताओं को ईईपीसी इंडिया-भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किए गए।

हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों को पुरस्कृत करने के 50 वर्ष पूरे होने पर ईईपीसी और आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 111 विजेताओं को बधाई दी।

उन्होंने 40 लाख कामगारों को रोजगार देने वाले इंजीनियरिंग क्षेत्र से अनुरोध किया कि वैश्विक इंजीनियरिंग मानकों और नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं, ताकि उनकी दक्षता अद्यतन होने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धा और लागत में सुधार प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इंजीनियरिंग उद्योगों का भूमि, श्रम और पूंजी के अधिकतम उपयोग के लिए स्मार्ट फैक्ट्रियां स्थापित करने का आह्वान किया। पुरी ने कहा कि ईईपीसी के 55 प्रतिशत सदस्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं।

नक्सली लीडर रमन्ना की हुई हार्ट अटैक से मौत?

» छत्तीसगढ़ में था रमन्ना का टेरर

बीजापुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे प्रमुख माओवादी नेता रमन्ना की कथित तौर पर मौत हो गई है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि पुलिस को विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले सप्ताह दिल का दौरा पड़ने से नक्सली नेता रमन्ना की मौत हो गई है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में माओवादियों की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। माओवादी अक्सर अपने बड़े नेताओं की मृत्यु पर बयान जारी करते हैं।

चेरला इलाक़े के हाट बाज़ारों में पहुँचे जहां ग्रामीणों के माध्यम से तेलंगाना पुलिस को खबर मिली है की नक्सली कमांडर रमन्ना का अंतिम संस्कार पालागुड़ा नाम के गाँव में कर दिया गया है। ग्रामीणों से इस मामले में और भी पुलिस ने जानकारी ली है पर पुरे मामले पर तेलंगाना पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरअसल नक्सली कमांडर रमन्ना की मौत की पुष्टी काफ़ी मुश्किल भरा काम माना जा रहा है वही पुरे मामले में नक्सलियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेस विज्ञप्ति का इंतज़ार सभी को है । बहरहाल तेलंगाना के कोत्तागुड़म पुलिस कप्तान सुनिल दत्त शर्मा को ग्रामीणों से रमन्ना की मौत की जानकारी के अनुसार रमन्ना की मौत ताड़मेटला इलाक़े के कुमड़तुंग गाँव में हूई थी। ग्रामीणों के अनुसार कोत्तागुड़म पुलिस ने भी रमन्ना की मौत पुष्टी की है।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना उर्फ रावलु श्रीनिवास की पिछले शनिवार की रात मौत हो गई। बीजापुर जिले के पामेड़ और बासागुड़ा गांव के मध्य जंगल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। सुंदरराज ने बताया कि रमन्ना की मौत की जानकारी को पुष्ट करने के लिए कई सबूत मिले हैं। लेकिन फिर भी इस संबंध में अधिक जानकारी ली जा रही है।

पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि रमन्ना माओवादियों के केंद्रीय समिति का सदस्य था। पिछले कुछ दशक से बस्तर क्षेत्र में हुई बड़ी घटनाओं का वह मास्टरमाइंड था। इनमें 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की मौत तथा वर्ष 2013 में दरभा घाटी नक्सली हमला शामिल है। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मारे गए थे। रमन्ना तेलंगाना के वारंगल जिले का निवासी था। छत्तीसगढ़ में उसपर 40 लाख रुपए का इनाम है। उसकी पत्नी सावित्री उर्फ सोढ़ी हिडमे एक स्थानीय आदिवासी महिला है। वह दक्षिण बस्तर में प्रमुख माओवादी नेता है तथा किस्टाराम एरिया कमेटी में सचिव के रूप में काम कर रही है।